उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुमाग-3

संख्या 587/XVIII(3)/2016-02(06)/2016 देहरादून, 10 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

मूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की घारा 30 की उपधारा (2) के साथ पठित प्रथम अनुसूची की कम संख्या 2 के कॉलम सं0 3 द्वारा प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गुणक द्वारा बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है, वह गुणक 2.00 (दो) होगा। साथ ही उक्त अधिनियम की घारा 30(1) के अनुसार कलेक्टर, सम्पूर्ण प्रतिकर का अवधारण करते समय शत्—प्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य अतिरिक्त तोषण (100 प्रतिशत सोलेशियम) की रकम अधिरोपित करेगा।

प्रदेश के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये सुदूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों में अधिग्रहण के दौरान पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन धनराशि का आंकलन, सम्बन्धित आयुक्त एवं प्रशासक के देखरेख में गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाधात आंकलन समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा। प्रदेश के सुदूरवर्ती जनजाति क्षेत्रों के निवासियों के रीति रिवाज, सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक धरोहर के दृष्टिगत पुनर्व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जायेगा।

डी0एस0 गर्ब्याल, संचिव। In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 587/XVIII(III)/2016-02(06)/2016, Dehradun, dated October 10, 2016 for general information:

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND RAJASWA ANUBHAG - 3

No. 5B7/XVIII(III)/2016-02(06)/2016 + Dated Dehradun, October 10, 2016

NOTIFICATION

Whereas powers conferred to the State Government to notify under sub section 2 of section 30 read with serial no.2, column no. 3 of first schedule of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), state government notify that in rural areas, the multiplying factor of the market value will be two (2.00). Along with, according to section 30(1) of the said act, the Collector, having determined the total compensation to be paid shall impose an extra "Solatium" amount equivalent to one hundred percent of the compensation amount.

By seeing the geographical condition of Uttarakhand state, during land acquisition in remote unapproachable areas, estimation of Rehabilitation & Resettlement (R-R) amount , will be estimated by expert group under R-R commissioner and administrator according to SIA report as per rule. For remotest scheduled tribe areas of the state, Rehabilitation & Resettlement shall be decided in keeping of view their customs, social structure, retrials and cultural heritage.

By Order,
D.S. GARBYAL,
Secretary.